

श्री नन्दासेन रावणकर ए

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विनय पत्राचार श्रीमाडेवी

तारीख हुकम

138  
2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

28/02/18

आधिवक्ता कृषीमाधी उपाधीत

कानूनिय रिपोर्ट होकर  
पत्रावली का प्रस्तुत हुई। पत्रावली  
दर्ज करिस्ट करे। आधिवक्ता कृषीमाधी  
की बहस जार्जना पत्र स्वयं पर सुनी  
गई। कानूनिय माधी। कृषीमाधी द्वारा  
प्रस्तुत जार्जना पत्र फर्द इत्यावेत सूची  
के साथ प्रस्तुत नकल आदेशिकाए जो  
आधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत  
बाद में धारित की गई है कि कौर  
आधारित कर बहस में निवेदन किया  
कि आधिवक्ता न्यायालय द्वारा उनके  
समक्ष प्रस्तुत जार्जना पत्र कस्यार्  
निषेधाया में सर्वप्रथम दिनांक 29/4/2011  
को एकपक्षीय आदेश कस्यार् निषेधाया  
इस संदर्भ का जारी किया गया था कि  
वाइवुलर माके के राजस्व रिकार्ड व  
माके की न्यायाधीनता कागामी तारीख  
पेशी दिनांक 17/5/2011 तक कागम  
रही बाते किन्तु आधिवक्ता न्यायालय  
के समक्ष कृषीमाधी के उपाधीत होने के  
पश्चात भी निरन्तर दिनांक 29/4/2011  
को धारित एकपक्षीय आदेश की मियाड  
बदारी का रही है। कानूनिय उ माधी। कृषीमाधी  
ने फर्द इत्यावेत के साथ प्रस्तुत नकल



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	132 <u>2018</u>	विनय पराशर / शीलादेवी हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए  2
------------	--------------------	--	--

वाड पत्र की कौर काकर्षित कर बेहम में  
 निवेदन किया कि यह पत्र वाडी द्वारा  
 अपने वाड में स्वीकार किया गया है कि  
 पुरन्गत काराजी में वादिना का 2/3 हिस्सा  
 तथा प्रतिवादी सरणा - 1 का 1/3 हिस्सा है  
 एवं पुरन्गत काराजी को वादिना ने मौके  
 पर मनबर कबुसार बाँट रखा है तथा  
 अपने हिस्से में कारि काम पर काबिल  
 होकर काश्त करती चली जा रही है।  
 प्रार्थी / अपीलार्थी प्रतिवादी स. 1 से वाड  
 में कांति उसके हिस्से 1/3 का हुआ  
 है किन्तु वाडीया द्वारा काधिल्लय न्यायालय  
 से सम्पूर्ण काराजी हेतु कस्बारी निषेधना  
 का आदेश प्राप्त कर ~~उस~~ प्रार्थी के इतशुदा  
 काराजी का उसके एक में नानान्तरण  
 खुलने से वांचित कर रहा है जिसकी  
 की वह इत करने के पश्चात काधिल्लय  
 है एवं जब अपने वादिना उक्त काराजी  
 को बेचान पर कामडा है। काकिनाथ क  
 प्रार्थी / अपीलार्थी ने हकारा दरान्  
 आदेश 39 नियम 3-ए लापता दीवानी  
 की कौर काकर्षित कर कर बेहम में  
 निवेदन किया कि न्याय का यह कावथक  
 सिद्धांत उक्त धारा के तहत दिया हुआ  
 है कि जो न्यायालय जिसके समक्ष प्रार्थना  
 पत्र कस्बारी निषेधना लाम्बित हो, वह  
 उसका निस्तारण 30 दिवस की अवधि



राजस्व अपील प्राधिकारी  
 जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	132 2018	विनय पराशर / शीलादेवी हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
			3

में कावचपत्र रूप से करे किन्तु इस प्रकरण में दिनांक 29/4/2011 को प्रथम बार पारित कस्वार्ड निषेधाज्ञा कादेश का निस्तारण कावच दिनांक तक नहीं किया गया है जो उक्त कादेश 39 नियम 3 ए का सीधे तौर पर उल्लंघन है जिससे ही कादेश तैर अपील तृतीय हो जाता है। उक्त: अपीलधीन कादेश दिनांक 29/4/2011 को निरस्त करमाया जावे।

हमने बहस कावचपत्र प्रार्थी / अपीलधीन पर जोर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सुश्रेष्ठ अधिकृत्य न्यायालय द्वारा दिनांक 29/4/2011 को प्रथम बार उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र कस्वार्ड निषेधाज्ञा में एकपक्षीय कस्वार्ड निषेधाज्ञा का कादेश पारित किया गया था, जिसके पश्चात दिनांक 09/9/2011 को अपीलधीन के उपायुक्त काकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी कावच दिनांक तक प्रार्थना पत्र कस्वार्ड निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं किया गया है जबकी कस्वार्ड निषेधाज्ञा के कादेश की मिलाड निरन्तर बहाववाली रही है। यहाँ यह उल्लेख करना भी



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

02

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म $\frac{132}{2018}$	विनय पराशर / श्रीमोडेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	---	--

आवक है कि वादिया द्वारा अपने वाद  
 में एवम् ने प्रतिवादी सख्या-1 का प्रस्ताव  
 ज़ाराजी में 1/3 हिस्सा स्वीकार है बाल्कि  
 यह भी स्वीकार गता है कि माँके पर  
 मन्बट के आधार पर दोनो पक्ष कावैज  
 काबत है ऐसेमे प्रतिवादी सख्या-1 द्वारा  
 अपने हिस्से 1/3 के बैचान को गलत नही  
 हस्तगत जा सकत एवं न ही हेला को  
 उसके उपयोग से वंचित रखा जा  
 सकत है। ऐसी स्थिति में अधिनियम  
 न्यायालय द्वारा प्रथम बार कस्वार्  
 निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के  
 पश्चात अन्तर सात वर्षों तक प्रार्थना  
 पत्र का निस्तारण नही करना आदेश  
 39 नियम 3 ए के विपरित होने से  
 अधिनियम न्यायालय द्वारा पारित आदेश  
 दिनांक 29/11/2011 की विधान्वीत  
 स्थागित रही जाती है तदनुसार चूंकी  
 प्रार्थना पत्र कस्वार् निषेधाज्ञा अधिनियम  
 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः  
 अपील इस स्तर पर ही उपरोक्त  
 अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर  
 प्रकरण अधिनियम न्यायालय को इस निर्देश  
 के साथ प्रलिपित किया जाता है कि वे  
 उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र कस्वार्  
 निषेधाज्ञा पर दोनो पक्षों की सुनवाई कर  
 30 दिवस की अवधि में गुणावगुण पर  
 निस्तारण करें। तदनुसार पत्रावली केसल सुनवाई  
 होकर वाद तत्काल समाप्त होकर है।



विनय पराशर  
 जयपुर